

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./

3551

/2022/रायगढ़, दिनांक :- 26.06.2022

प्रति,

महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन
कंपनी लि. गारे पेलमा कोल माइंस
सेक्टर- II, विद्युत भवन कटोल
रोड़ (नागपुर)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for the Gare Pelma Sector -II Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) Coal block is located in the Mand Raigarh coalfield of Raigarh district, Chhattisgarh area - 214.869 ha. - regarding.

संदर्भ:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 8-06/2022 FC दिनांक 02.06.2022
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-229/1279 रायपुर दिनांक 09.06.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Gare Pelma Sector -II: Coal Block has been allotted to Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) हेतु कुल क्षेत्र 214.869 हे. वन भूमि के लिए संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन दो पार्ट में तैयार किया जाना है जो निम्नानुसार है:-

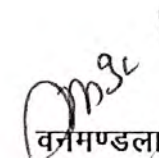
1. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में पार्ट A-1 से A-16 में दर्शित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त अनुरूप होगी जबकि B-1 से B-17 में दर्शित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन द्वितीय चरण स्वीकृति के पश्चात पालन किया जाकर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है।
2. प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक A1 (i) अनुसार सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्ष 2022-23 के लिए अद्यतन दर राशि रु. 8,78,787/- अनुसार व्यपवर्तित भूमि के समतुल्य निजी भूमि रकबा 214.869 अनुसार राशि रु. 18,88,24,084.00 (रुपये अठारह करोड़ अठासी लाख चौबीस हजार चौरासी मात्र) तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का 25 प्रतिशत राशि मृदा संरक्षण हेतु राशि रु. $18,88,24,084 \times 25\% = 4,72,06,021.00$ (रुपये चार करोड़ बहत्तर लाख छः हजार इक्कीस मात्र) वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें तदुपरांत समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

1. प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक A 3 के पालन में समादेश याचिका (सी) क्रमांक 202/1995 के अंतर्गत आई.ए. क्रमांक 556 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 एवं दिनांक 06.01.2022 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्रांक दिनांक 5-3/2011-FC (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव हेतु व्यपवर्तित की जाने वाली 214.869 हे. मे से सघन वन रकबा 99.735 हे. के लिए इको वेल्यु क्लास-III सघन वन प्रति हे. 1228590.00 अनुसार राशि रुपये 12,25,33,424.00 (रुपये बारह करोड़ पच्चीस लाख तैतीस हजार चार सौ चौबीस मात्र) एवं खुला वन भूमि रकबा 115.134 हे. के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) राशि इको वेल्यु क्लास-III खुला वन अनुसार प्रति हे. 957780.00 अनुसार राशि रुपये 11,02,73,043.00 (रुपये ग्यारह करोड़ दो लाख तिहत्तर हजार तिरालीस मात्र) कुल राशि रुपये 23,28,06,467.00 (रुपये तेईस करोड़ अठाईस लाख छः हजार चार सौ सड़सठ मात्र) वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक A 12 के पालन में सेपटी जोन रकबा 29.730 हे. लिए राशि रु. 2,61,26,338.00 (रुपये दो करोड़ इक्कसठ लाख छब्बीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।
5. प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक A 6 से शर्त क्रमांक A 14 के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें।

उक्त स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र एवं दस्तावेज संलग्न कर 04 प्रतियों में प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।




वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

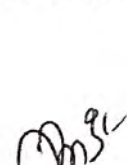
पृ. क्रमांक/तक.अधि./

3522

2022/रायगढ़, दिनांक :- 20-06-2022

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।


वनमण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र/ भू-प्रबंध/खनिज/331-229/1279

रायपुर, दिनांक 09/06/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषय:-

Proposal for non-forestry use of 214.869 ha. of forest land in favour of M/s Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector - II Open cast Coal Mining Project in the Mand Raigarh Coalfield, in District Raigarh (Chhattisgarh) - reg. .

पंजीयन क्रमांक:- FP/CG/MIN/20495/2016

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र F.No. 8-06/ 2022 FC दिनांक 02.06.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न)।

विषयांकित प्रस्ताव की प्रथम चरण स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.06.2022 को जारी की गई है। उक्त स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन को दो पार्ट में तैयार किया जाना है।

1. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति के पार्ट A-1 से A-16 में दर्शित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त अनुरूप होगी जबकि पार्ट B-1 से B-17 में दर्शित बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन द्वितीय चरण स्वीकृति के पश्चात पालना कराया जाना है।

2. संदर्भ पत्र के शर्त क्रमांक- A1 (i) अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एवं शर्त क्रमांक- A 1 (ii) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की 25 प्रतिशत राशि मृदा संरक्षण के लिए अद्यतन दर से आवेदक संस्थान से वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें तथा तदुपरांत शीघ्र संदर्भ पत्र के समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन मय पृथक - पृथक वचन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें। वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं भूजल संरक्षण कार्य की समेकित योजना प्रस्तुत की जाएगी।

3. शर्त क्रमांक - A 1 (iv) अनुसार अधिसूचना प्रस्ताव मय कलेक्टर की अनापत्ति तथा नोईयत परिवर्तन पृथक से प्रेषित करें।

4. शर्त क्रमांक- A 3 अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि दिनांक 06.01.2022 से जारी नवीन दर से वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।

5. शर्त क्रमांक- A 12 अनुसार सेफ्टी जोन की राशि वेब पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराकर इस कार्यालय को सूचित करें।

6. शर्त क्रमांक - A - 6 से शर्त क्रमांक - A- 14 के अनुसार योजना तैयार कर प्रेषित करें।

उक्त प्रस्ताव में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें। समस्त योजनाओं का मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त अनुमोदन करेंगे तथा योजना वर्ष 2022-23 से प्रारंभ होगी एवं तदनुसार दर गणना हेतु ली जावे, तीन प्रतियों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वनमंडलाधिकारी रायगढ़ इस संबंध में डिमाण्डनोट जारी करें।

संलग्न:-

संदर्भ पत्र की छाया प्रति

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-245/1280
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 09/06/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि. (महाजेनको), प्लेट नं.-12, एम.एस.डी.-2 बिल्डिंग, जे.पी. एल. कालोनी, ऊर्जा नगर, सावित्री नगर, तहसील. तमनार, रायगढ़, छत्तीसगढ़-496108 (Email- secivilgp2@mahagenco.in)

अ.प्र.मु.व.स. (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

File No. 8-06/2022-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jorbagh Road, Aliganj,
New Delhi - 110003.
Dated: 2nd June, 2022

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhavan,
New Raipur (CG).

Sub: Proposal for non-forestry use of 214.869 ha of forest land in favour of M/s Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector -II Opencast Coal Mining Project in the Mand Raigarh Coalfield, in District Raigarh (Chhattisgarh) – reg.

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter no. F-5-26/2021/10-2 dated 19.04.2022 on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and letter no. Bhu-Praband/Khanij/331-245/1025 dated 10.05.2022 forwarding additional information as sought by the Ministry vide its letter of even number dated 22.04.2022 and to say that the proposal has been examined by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section - 3 of the aforesaid Act.

After careful examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the Central Government hereby accords approval for non-forestry use of 214.869 ha of forest land in favour of M/s Maharashtra State Power Generation Company Limited (MAHAGENCO) for Gare Pelma Sector -II Opencast Coal Mining Project in the Mand Raigarh Coalfield, in District Raigarh (Chhattisgarh) subject to fulfilment of the following conditions:

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval

1. Compensatory Afforestation:

- The Compensatory afforestation over equivalent non-forest land, shall be raised by the State Forest Department at the project cost. At least 1000 saplings per ha shall be planted over admissible CA land. If this not possible to plant these many seedlings in the identified NFL, the balance seedlings will be planted in degraded forest land as per the prescription of the Working Plan at the cost of the User Agency. Detail of such degraded forest land proposed for afforestation of surplus trees shall be submitted to the Ministry before Stage-II approval along with afforestation scheme, suitability

mining

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रका)
छत्तीसगढ़, रायपुर

Dec.

पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू-प्रका)
नया रायपुर छ.ग.
नया क्र. 1384
नांक 06/06/2022

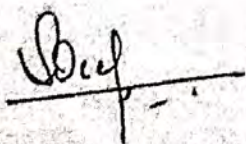
- certificate, KML files, etc. In such cases CA cost will be revised and duly approved by the competent authority and deposited online in the CAF managed by the CAMPA;
- ii. 25% of the CA cost additionally will be spent towards soil and moisture conservation activities in the proposed CA area as per site requirement and deposited in CAF;
 - iii. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;
 - iv. The non-forest land identified for CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and subsequently notified by the State Government as RF under Section - 4 or PF under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act before Stage-II approval. A copy of the final Notification shall be submitted along with the compliance of Stage-I approval;
2. The KML files of diverted area, the CA areas, the proposed SMC treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage II approval;
 3. The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the guidelines issued by this Ministry vide its letters No. 5-3/2011-FC (Vol.) dated 06.01.2022 read with letter dated 22.03.2022. The requisite funds shall be transferred through online portal into National Authority (CAMPA) account of the State Concerned; new NPV guidelines;
 4. Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of CAMPA pertaining to the State concerned through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>);
 5. Mine is located close to Kelo River flowing in the area. Numbers of mines are operational in the area which may cause threat to hydrological regime viz. Kelo river and its rivulet, therefore, a study to assess the hydrological regimes and cumulative impact of mining and industrial activities being undertaken in the GarePebma area, on the hydrological regimes of area shall be undertaken in consultation with the Water Resource Department and the same shall be submitted along with considered opinion of Water Resource Department of the State before Stage-II approval. Recommendation to be made in the study shall be implemented by the State from the funds to be realized from the agencies, on pro rata basis, working in the area. The user agency shall also keep adequate area, as per the guidelines of DGMS (Director General of Mine Safety), along the bank of River Kelo as intact and no mining should be carried out in this area. Embankment should be constructed to ensure protection of river and its hydrology from the mining.
 6. A Soil and Moisture Conservation (SMC) work plan to mitigate the impact of the proposed mining activity on the local rivulets (nallah) shall be prepared by the user agency in consultation with the State Forest Department and the same shall be submitted along with Stage-I compliance. Cost of implementation of the provisions of the said Plan will be deposited into the

Def

- CAMPA and the same shall be intimated to the Ministry before Stage-II approval.
7. Final Mining Plan, after rectifying the detail of forest area involved in the mining leases and being approved under the Forest (Conservation) Act, 1980, shall be submitted to the Ministry before Stage-II approval.
 8. Area of green belt proposed by the user agency should be increased to cover maximum possible area under the green belt in the lease area of the agency and a report containing the detail of areas proposed to be kept as green belt should be submitted before Stage-II approval.
 9. Following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertaken in the lease area by the User Agency under the supervision of the State Forest Department. Approved scheme/plan shall be submitted to the Ministry along with compliance of Stage-I approval:
 - i. Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three year with effect from the issue of Stage-II clearance in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department.
 - ii. Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;
 - iii. Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;
 - iv. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28° ; and
 - v. No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.
 10. User agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located in the area within 100 meter from outer perimeter of the mining lease. The plan for plantation and SMC activities will be prepared and submitted to MoEF & CC before Stage-II Clearance;
 11. The User Agency shall prepare a list of existing village tanks and other water bodies with GPS co-ordinates located within five km from the mine lease boundary. This list is to be duly verified by the concerned Divisional Forest Officer. The User Agency shall regularly undertake desilting of these village tanks and other water bodies so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies. A detailed approved plan for desilting of identified ponds and water bodies to be prepared in consultation with forest department and shall be submitted to MoEF & CC before Stage-II approval;
 12. **Safety Zone Management:** Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry's guidelines:
 - i. User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5 meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars

Def.

- inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department;
- ii. Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;
 - iii. Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and to ensure dense canopy in the area, regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;
 - iv. Afforestation on degraded forest land to be selected elsewhere, measuring one and a half times the area under safety zone, shall also be done at the project cost under the supervisions of the State Forest Department. The degraded forest land (DFL) so selected will be informed to the MoEF & CC with shape files before Stage-II approval and afforestation will be done within three years from the date of Stage-II clearance and maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department; and
 - v. The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;
13. The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;
14. *Elephant/Wildlife Management Plans should be revised and prepared keeping in view the locality factors, occurrence of wildlife, management interventions required for areas. State Government may also get the revised Plan verified by an institute of repute. Cost of implementation of the Plan so finalized shall be deposited into State CAMPA and detail of the same along with approved Plan shall be submitted to the Ministry before Stage-II approval.*
15. State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence, along with compliance of Stage-I approval, as prescribed by this Ministry's letter No. 11-9/1998-FC (Pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013, in support thereof;
16. *Proposal involves displacement from non-forest land. A copy of approved R&R plan, prepared in consonance with the R&R policy of the State, shall be submitted along with the compliance of Stage-I approval. It shall be ensured that no rehabilitation is proposed on the forest land; and*
17. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- B. Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**
1. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;



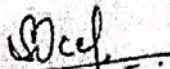
2. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;
3. Trees should be felled in phased manner as per the requirement in the approved Mining Plan with prior permission of concerned DFO;
4. The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;
5. The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on re-grassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;
6. The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the concern Addl. Principle Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities area satisfactorily executed.
7. Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended and the Rules framed there-under;
8. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;
9. No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;
10. The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates;
11. The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;
12. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;
13. No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;
14. The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;
15. Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and

Beef

16. The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours faithfully,


(Sandeep Sharma)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. Principal Chief Conservator of Forest (PCCF) Aranya Bhavan, Sector 19, North Block, New Raipur- 492002 Chhattisgarh.
2. Regional Officer, Integrated Regional Office, MoEF&CC, Naya Raipur
3. The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Jail Road, Aranya Bhavan, Raipur.
4. User Agency
5. Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF&CC
6. Guard file.